परेशान करते है। गंतव्य तक माल नहीं पहुंचता और माल कम जाने की स्थिति में 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्लेम बरसों बाद मिलता है जिसमें कई अधिकारियों की पूजा करनी पड़ती है। दस नगों में से नौ पहुंचने पर 4 रुपए रोज़ चालू हो जाता है। दसवां नग न पहुंचना क्या रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है? तो साक्षरता का प्रचार कैसे होगा। रेल भाड़े में निरंतर वृद्धि से रही है और पुस्तकों पर कोई छूट नहीं है। अंग्रेज सरकार 50 प्रतिशत छूट देती थी लेकिन हमारी सरकार पुस्तकों के फ्रेट में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं देती है, जब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह नीति थी कि पुस्तकों पर हर तरह की छूट मिलनी चाहिए।

डाकघर में एक महीने से बैग नहीं है, पोस्टमास्टर से मिले लेकिन नतीजा जीरो है। पैकेट, रजिस्ट्री, वी.पी.पी को लेकर हम मारे-मारे फिरते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। कहते हैं जाओ ऊपर मिनिस्टर से कहो, पहले बैग भेजो, पोस्टिंग तब करेंगे। अनुशासन ही देश को राह पर लाता है। नैतिकता से मानव प्रगति करता है। नैतिक मूल्यों का जो पतन इस देश में हो रहा है उसे आप जैसा शिक्षाविद, सुसंस्कृत सांसद ही संसद में आवाज उठाकर बचा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पुस्तकें उद्योग नहीं हैं, पुस्तकें ज्ञान हैं। मनोरंजन के और भी साधन हैं। टी.वी. है, सिनेमा है। लेकिन अगर चिंतन और विचार कहीं है तो वह पुस्तकों में है, और वह पुस्तकें नहीं, जो आज लिखी जा रही हैं। वह पुस्तकें हैं जो कि हमारे लिए राष्ट्रीय धरोहर हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए सरकार गंभीरता से कदम उठाए। रेलवे में पुस्तकों को भेजने के लिए निश्चित रूप से सुविधा होनी चाहिए, फ्रेट में कमी होनी चाहिए। यह दूसरे माल और असबाब की तरह से नहीं जाना चाहिए। इसी तरह डाकघरों में भी पुस्तकों के लिए रियायत होनी चाहिए। जो जवाहर लाल नेहरू जी के समय मिलती थी वह आज नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ एक अंतिम बात यह कहना चाहूंगा कि चुनाव जब सामने आ रहे हैं तो हो सकता है कि कागज के दाम बढ़ेंगे-पोस्टर वगैरह के लिए। लेकिन जहां हम साक्षरता का प्रचार कर रहे हैं, जहां 40 प्रतिशत लोग जिस देश में निरक्षर हैं, उस देश में तब तक काम नहीं होगा जब तक कि इसके लिए साधन सरकार मुहैया नहीं करे। साधन सरकार मुहैया करे। प्रकाशक अपनी जिम्मेदारी समझे, कम से कम कीमत रखे। साथ-साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो विदेशी पुस्तकें आती हैं, उसमें साइंस की, टैक्नोलोजी की किताबें आनी चाहिए। यह जरूरी है। लेकिन यह जो सस्ते उपन्यास भरे रहते हैं स्टेशनों पर और हवाई अड्डों पर, इससे कौन सा मानसिक विकास हो सकता है? मनोरंजन हो सकता है। करोड़ों-करोड़ रुपया इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा में विदेशों में चला जाता है। इसलिए इस पर बैन लगना चाहिए और अनिवार्य पुस्तकें आनी चाहिए। चाहे वह टैक्नोलोजी की हों, साइंस की हों, दूसरे विषयों की हों, मैडिसिन की हों। यह बहुत जरूरी है। लेकिन मनोरंजन और आम सैक्स की, हिंसा की जो इतनी अधिक पुस्तकें चली आ रही हैं, अम्बार का अम्बार आप देखते हैं, यह बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से सरकार तक जो हमने बात पहुंचाई है, उस पर सरकार गंभीरता से ध्यान देगी।

Threat to the Buildings situated at Chittaranjan Avenue, Calcutta due to

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बहुत गंभीर समस्या की ओर सरकार का और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कलकत्ता महानगर में मैट्रो रेलवे का काम कब तक चलता रहेगा, यह तो राम जी जानें। लेकिन अभी चितरंजन एवेन्यू के गिरिश पार्क से लेकर महात्मा गांधी मार्ग तक के अंचल में जो स्थिति है, वह अत्यन्त भयावह है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वहां मैट्रो रेलवे के अधिकारियों और इंजीनियरों की गलतियों के कारण बार-बार जमीन धंस रही है। कोई एक समय था जब चितरंजन एवेन्यू कलकत्ता का सबसे बड़ा राजमार्ग था, सबसे प्रतिष्ठित राजमार्ग था। उस प्रतिष्ठित राजमार्ग की यह दयनीय स्थिति है कि हर चौथे-पांचवें महीने कहीं न कहीं की भूमि धंस जाती है। कभी वहां का जो एक पैट्रोल पम्प है, वह धंस गया। वहां जो मछुआ बाजार के पास की बस्ती है, वह धंस गई। वहां जो सदन के बगल वाला मकान था वह भी धंस गया। यह सब तो हुआ। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, पिछली एक जुलाई, 1994 को 191, चितरंजन एवेन्यू का छह मंजिला मकान ताश के महल की तरह भर-भराकर गिर गया। उस दिन बारह बजे तक मैट्रो रेल के सब इंजीनियर कहते रहे कि यह मकान सुरक्षित है, जबकि वह रात के दस बजकर 29 मिनट पर गिर पड़ा। यह तो कहिए कि वहां के जो तमाम रहने वाले थे, दरारों को बढ़ते हुए देखकर चले गए थे। इसलिए प्राण हानि तो नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हो गई।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): उस समय मैट्रो रेलवे के नीचे काम चल रहा था?

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सुरक्षा की दोनों दीवारें बहुत कमजोर हैं, एक छेद था।

उसमें से सारा पानी नीचे में चला गया। जब वह मकान गिरा तो कलकत्ता नगर निगम के चीफ इंजीनियर और मैट्रो रेलवे के चीफ इंजीनियर के बीच खूब-विवाद होने लगा। एक कहते हैं कि तुम्हारी गलती के कारण पानी रिसा और दूसरे कहते हैं कि तुम्हारे छेद के कारण पानी रिसा। लेकिन सच्चाई यह है, माननीय रामेश्वर ठाकुर जी जानते हैं, वे कलकत्ता के रहने वाले हैं, कि उस पूरे अंचल में भय व्याप्त है। 45 मकान जर्जर घोषित कर दिए गए। इस प्रकार गिरने के बाद पांच मकान और जर्जर घोषित कर दिए गए। मेरी मांग है कि जो जर्जर मकान हैं, मैट्रो रेलवे के इंजीनियर उनको या तो मरम्मत करें या वहां रहने वालों को कोई वैकल्पिक स्थान दें और वहां उनकी व्यवस्था करें। जो मकान वहां गिरा है, उसमें कई दुकाने थीं। वहां दुकान मिलना मुश्किल है। वहां रहने वालों के लिए कोई और विकल्प नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा मकान कैसे गिरा? उसमें रहने वाले प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक दुकानदार को तीन-तीन लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और जो 52 मकान बिल्कुल जर्जर घोषित किए गए हैं, उनकी देख-रेख और उनके रख-रखाव का कोई विशेष प्रबंध होना चाहिए। मैं चाहता था कि माननीय रेल मंत्री जी यहां रहते लेकिन वह चले गये हैं, माननीय रामेश्वर ठाकुर जी कलकत्ता के पुराने नागरिक होने के कारण मैं समझता हूं कि अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे और वे मईद साहब से बात करेंगे।

श्री शंकर दयाल सिंह: शास्त्री जी, नागरिक तो यह बिहार के हैं, यह कहिए कि कलकत्ता में रहे हैं।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: वे सुन ही नहीं रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सईद साहब से अनुरोध करें कि यह जो इतना बड़ा हादसा हो गया है, कलकत्ता में, उसकी सुव्यवस्था हो और जो 52 मकान किसी भी समय गिर सकते हैं, उनकी रक्षा हो, उसकी जांच पड़ताल हो कि क्या हो सकता है। वहां के नागरिकों के लिए कोई विकल्प हो, व्यवस्था हो। मैं माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस क्षेत्र के नागरिकों को भयमुक्त करेगी। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): I think the hon. Minister would request the Minister for Railways to look into this aspect, otherwise there will be loss not only of property but also of human beings.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPTT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRl RAMESHWAR THAKUR) Sir. I quite appreciate the sentiments of the hon. Member. As the hon. Member had said, I have lived in that area f more than 12 years and I have seen the position recently I will convey the feelings and suggestions of the hon Member to the hon Minister for Railways.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1994

THE SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 23rd August, 1994. agreed without any amendment to the Motor Vehicles (Amendment) Bill. 1994, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August, 1994"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): The House is now adjourned till tomorrow.

> The House then adjourned at thirt seven minutes past seven of the clo till eleven of the clock on Wednesd; the 24th August, 1994